सं. ए-45011/3/2022-प्रशासन III
भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को सितंबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

रविन्द्र 10/11/22

(रविंदर कुमार)
निदेशक (प्रशा. IV और समन्वय)
दूरभाष नं. 2309-5244

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीएफ़एस) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीपीई) के प्रधान निजी सचिव
11. श्री वीनागेश्वरन अनंत., मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ।(वित्त)
14. श्री टी. नटराजन, अपर सचिव (प्रशासन/समन्वय/सीएंडसी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी-20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-।।)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्तियां और सीबीडीसी)
16. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (एफ़बी एंड एडीबी) एंड सीवीओ
17. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी) /संयुक्त सचिव (आईएनवी)/ संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल – 2022

सं.ए-45011/3/2022-प्र.शा.III

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
***

विषय: सितंबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृहत आर्थिक सिंहावलोकन:

पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि: वित्त वर्ष 2022-23 के पहले छह माह में भारत की वृद्धि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ शुरू हुई, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के अगस्त तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46.8% अधिक थी। कर अनुपालन में सुधार के बाद मजबूत राजस्व सृजन द्वारा पूंजीगत व्यय के स्तर में वृद्धि की गई। चालू वर्ष के अगस्त तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजटीय स्तर का 32.6% था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा अधिक है।

विस्तारक क्षेत्र (एक्सपेंशनरी ज़ोन) में उत्पादन जारी रहा: पीएमआई उत्पादन सितंबर 2022 में विस्तारक क्षेत्र (एक्सपेंशनरी ज़ोन) में जारी रहा, जिसमें नई व्यापार वृद्धि, मांग लचीलापन और विस्तारित परिचालन क्षमताएं थी। इसके अलावा, औद्योगिक धातुओं की कीमतों में गिरावट के कारण इनपुट लागत मुद्रास्फीति 23 महीने के निचले स्तर पर आ जाने के कारण कारोबारी धारणा भी बढ़ी, जिससे निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के मुनाफे में वृद्धि हुई।

विकास को बढ़ावा देने के लिए सेवा क्षेत्र: अप्रैल-सितंबर की अधिकांश अवधि के लिए, संपर्क-आधारित सेवा क्षेत्र ने रूकी हुई मांग को बढ़ावा देकर विकास को काफी हद तक बढ़ाया है। पर्यटन उद्योग ने पिछले छह महीनों में अच्छी प्रगति की है, जबकि भारत में आयुष वीजा और हील जैसी नई सरकारी पहल आने वाले समय में वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार के बड़े हिस्से को हासिल करने में मदद कर सकती है।

सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली ने विकास प्रदर्शन का समर्थन किया: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत विकास प्रदर्शन को एक अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली द्वारा समर्थित किया गया है, जिससे खुदरा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋण संवितरण में वृद्धि देखी गई है। गैर-खाद्य ऋण वृद्धि मार्च 2022 में 8.7% से लगभग दोगुनी होकर सितंबर 2022 में 16.4% हो गई, जो न केवल वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के विकास में तेजी को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में भी निरंतर वृद्धि की प्रत्याशा को दर्शाती है। उद्योगों को ऋण में वृद्धि से ईसीएलजी योजना द्वारा सहायता प्राप्त एमएसएमई के बैंक ऋण में वृद्धि हुई है।

मुद्रास्फीति आरबीआई छूट सीमा से ऊपर बनी हुई है: औसत थोक और खुदरा मुद्रास्फीति, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में क्रमशः 16.1% और 7.3% थी, वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में घटकर क्रमशः 12.4% और 7.04% हो गई है। विशेष रूप से, खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-सितंबर की पूरी अवधि में लगभग 7% पर स्थिर रही है। सितंबर में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति घटकर 10.7% हो गई और अब सितंबर में सीपीआई मुद्रास्फीति 7.4% के बहुत करीब है, इनपुट लागत की निकासी को काफी हद तक हासिल किया गया प्रतीत होता है, जिससे बाद में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।

एफडीआई अंतर्वाह मजबूत बना रहा: अप्रैल-जुलाई के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष 2021-22 में 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर चालू वर्ष में 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फेड द्वारा नीति गत दरों में बढ़ोतरी के बावजूद, एफपीआई के बहिर्वाह में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही की तुलना में गिरावट आई, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ निवल खरीदार बन गए।

सुस्त वैश्विक विकास से भारत के बाहरी क्षेत्र पर अनिश्चितता का एक दौर आया: भारत के निर्यात में वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में गिरावट देखी गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, उन्नत देशों में उपभोक्ता खर्च में गिरावट, और आक्रामक मौद्रिक नीति की सख्ती, आने वाले वर्ष में एक धूमिल वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के सभी संयोजन थे। धीमे निर्यात और सतत आयातों ने व्यापारिक व्यापार घाटा वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 76.3 बिलियन डॉलर से वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 148.5

बिलियन डॉलर तक लगभग दोगुना कर दिया है। बढ़ते व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) चौथी तिमाही: 2021-22 में जीडीपी के 1.5% से बढ़कर 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी का 2.8% हो गया है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: इस समय, विकास और स्थिरता पर दुनिया की तुलना में भारत को कम चिंता हो सकती है। फिर भी, पिछले छह महीनों ने भारत के लिए भी अनिश्चितता बढ़ा दी है जैसा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए है। आईएमएफ ने 2022 में विश्व उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को अप्रैल में 3.6% से संशोधित कर अक्टूबर में 3.2% कर दिया है, जबकि भारत के अनुमान को 8.2% से घटाकर 6.8% कर दिया गया है।

1. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(क) सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री ने फिनटेक में विनियामक सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के बीच फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी का दौरा किया।

(ख) आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना, 2022 के लिए दिशानिर्देश और आवेदन प्रपत्र जारी किए गए थे।

(ग) अवसंरचना वित्तपोषण, अवसंरचना कार्यान्वयन और पीपीपी प्रोत्साहन के तहत मौजूदा अपेक्षित पहलों के माध्यम से अवसंरचना के विकास में प्रगति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित राज्यों के साथ केंद्रित कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

- o 30 सितंबर, 2022 को वाराणसी में बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ।
- o 9 सितंबर, 2022 को चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्यों के साथ |

(ii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

(क) पैन सिटी (चंडीगढ़) परियोजना के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी एजेंस फ्रांसिस डी डेवलपमेंट (एएफडी) से 48 मिलियन यूरो का ऋण।

(ख) अहमदाबाद मेट्रो परियोजना चरण-2 के लिए के एफ डब्ल्यू से 100 मिलियन यूरो का ऋण।

(ग) एएफडी से दो किश्तों (पहली किश्त 100 मिलियन यूरो और दूसरी किश्त 111 मिलियन यूरो-अहमदाबाद मेट्रो परियोजना चरण-2) में 211 यूरो का ऋण।

(घ) 1191 मिलियन यूरो के औपचारिकरण के लिए वित्तीय सहयोग (एफसी) समझौता, 90.41 मिलियन यूरो टीसी प्रतिबद्धता के औपचारिकरण के लिए एफसी प्रतिबद्धता और तकनीकी सहयोग (टीसी) समझौता।

(iii) इस महीने के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी और अवसंरचना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ग) अनुबंध डिजाइन, बोली प्रक्रिया, वार्ता, अनुबंधों की निगरानी, मुकदमेबाजी को कम करने और प्रबंधित करने पर राजकोषीय नीति, लेखांकन और वित्त विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iv) अवसंरचना वित्त सचिवालय (आईएफएस) द्वारा एक हितधारक कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था

(v) उपक्रम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए विनियामक और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए जांच करने और उचित उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

(vi) माननीय वित्त मंत्री ने इस महीने के दौरान निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:-

(क) श्री मख्तार डियोप, प्रबंध निदेशक, आईएफसी और कार्यकारी उपाध्यक्ष -आईएफसी के साथ बैठक

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक (एमडी) सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता और भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए बैठक।

(ग) उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उप-प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहली भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक (आईएसएमआर)।

(घ) पूर्व चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों, मौजूदा वित्तीय/ऋण सूचना प्रणालियों की दक्षता में सुधार आदि पर चर्चा करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक।

(vii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं या इनमें भाग लिया गया।

(क) भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच परामर्श वार्षिक अनुच्छेद-IV, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों, सुधार पहलों और विकास संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए है।

(ख) घने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड-स्केल बैटरी प्रणालियों सहित डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संस्थागत तंत्र (आईएम) की 21 वीं बैठक।

(ग) नए आत्मनिर्भर भारत में जीआईएफटी आईएफएससी की रणनीतिक भूमिका और जीआईएफटी-आईएफएससी के अंतर-नियामक मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक।

(घ) 2023 में जी 20 की भारतीय प्रेसीडेंसी के दौरान वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ एफएसबी के संभावित योगदान और कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक।

(ङ) वैश्विक दृष्टिकोण, नीतिगत प्राथमिकताओं, एमडी के वैश्विक नीतिगत एजेंडा (जीपीए), आईएमएफसी विज्ञप्ति के निर्माण खंडों और वार्षिक बैठक 2022 की व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए आईएमएफसी प्रतिनिधियों की बैठक।

(च) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों पर विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति की 132वीं बैठक।

(छ) महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष (एफआईएफ) के गवर्निंग बोर्ड की वाशिंगटन, डीसी में विश्व बैंक के मुख्यालय में (हाइब्रिड प्रारूप में) पहली बैठक।

(ज) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जारी परियोजनाओं के लिए टीपीआरएम।

(झ) जापान के टोक्यो में आईडीए20 शुभारंभ कार्यक्रम।

(ञ) आर्थिक कार्य विभाग की वीजीएफ योजना के तहत वीजीएफ समर्थन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे (4 समूहों में) पर विचार करने के लिए 43 वीं ईसी बैठक।

(ट) प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते के तहत निवेश अध्याय पर भारत और कनाडा के बीच पहले दौर की बातचीत।

(ठ) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड की दूसरी बोर्ड बैठक।

(ड) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) की 31वीं बोर्ड बैठक।

(ढ) हाल के आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों और जी-20 के वित्त मंत्रियों को सौंपी जाने वाली रिपोर्टों की स्थिति के आलोक में वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए एफएसबी की बैठक।

(ण) जी 20 वित्तीय सुधारों और एससीएसआई 2023 कार्य प्राथमिकताओं के प्रभावों संबंधी मूल्यांकन पर चर्चा करने के लिए मानक कार्यान्वयन पर एफएसबी स्थायी समिति की बैठक।

(त) ऊर्जा क्षेत्र की रणनीति तथा 2023 व्यापार योजना और बजट सहित एआईआईबी के नीतिगत मुद्दों और निवेश संचालन पर विचार करने के लिए एआईआईबी के निदेशक मंडल की बैठक।

(थ) एनडीबी पर वित्तीय बाजारों में हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव और निहितार्थ, एनडीबी की सदस्यता विस्तार, ब्रिक्स एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और निधियन अद्यतन (फंडिंग अपडेट) सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एनडीबी निदेशक मंडल की बैठक।

(द) रोम स्थित कार्यकारी बोर्ड, आईएफएडी का, रोम, इटली में136 वां सत्र।

(ध) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) (एडीएफ-16) के साथ तकनीकी सत्र

(न) संसाधन जुटाने पर चर्चा के लिए अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) (एडीएफ-16) के साथ बैठक।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना

शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	01
विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा	:	07